

19 लोगों की मौत के बाद हरकत में आया प्रशासन दुर्गा पूजा भगदड़ की जांच के लिए एसआईटी गठित

सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनंदिता रॉय सरस्वती करेगी जांच की अगुवाई, तीन महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट; आयोजकों से लेकर सरकारी एजेंसियों तक की भूमिका की होगी पड़ताल कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल के पास 17 अक्टूबर को हुई दुर्गा भगदड़ में 19 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार ने घटना की विस्तृत जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है। इस दर्दनाक हादसे ने दुर्गा पूजा जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन तैयारियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल की ओर से 21 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार, कलकत्ता हाईकोर्ट के पारामर्श से गठित एसआईटी की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनंदिता रॉय सरस्वती



द्वारों और निकास मार्गों पर दबाव बढ़ जाता है। ऐसे आयोजनों में भीड़ की संभावित संख्या का आकलन, रास्तों की पर्याप्त चौड़ाई, बैरिकेडिंग, पुलिस की तैनाती और आपातकालीन निकासी की योजना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। चोरबागान पंडाल के पास हुई भगदड़ के

करेगी। जांच दल यह पता लगाएगा कि घटनास्थल पर कितने लोग मौजूद थे, भीड़ का दबाव किस दिशा में बढ़ा और लोगों के प्रवेश तथा बाहर निकलने के लिए उपलब्ध रास्ते पर्याप्त थे या नहीं। यह भी देखा जाएगा कि बैरिकेडिंग किस प्रकार की गई थी, लोगों को कतारों में आगे बढ़ाने की व्यवस्था कैसी थी और आपात स्थिति में भीड़ को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध थे या नहीं। आयोजन स्थल की सुरक्षित क्षमता और वास्तविक भीड़ के बीच अंतर का आकलन भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। यदि निर्धारित क्षमता से अधिक लोग मौजूद थे, तो यह पता लगाया जाएगा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए और क्या संबंधित अधिकारियों को स्थिति की गंभीरता का समय रहते अंदाजा हो गया था। भगदड़ की घटनाओं में कई बार अचानक

घटना की वास्तविक परिस्थितियों को समझने के लिए एसआईटी तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्य भी जुटाएंगी। इसमें घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, मोबाइल फोन से बनाए गए वीडियो, फोरेंसिक चिकित्सा रिकॉर्ड की जांच शामिल होगी। इन साक्ष्यों के आधार पर घटनाक्रम की समयरेखा तैयार करने और यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि भगदड़ किस समय शुरू हुई, भीड़ किस दिशा में बढ़ी और राहत कार्य कितनी तेजी से शुरू किए गए। मौसम संबंधी चेतावनियों और सार्वजनिक उद्घोषणाओं के रिकॉर्ड से यह भी समझने का प्रयास होगा कि आयोजकों तथा प्रशासन को परिस्थितियों की जानकारी किस समय मिली थी और उसके बाद क्या कदम उठाए गए। जांच का दायरा केवल पूजा आयोजकों

तक सीमित नहीं रहेगा। एसआईटी आयोजकों, निजी सुरक्षा कर्मियों, स्वयंसेवकों, पुलिस, एंबुलेंस सेवाओं, अस्पतालों, अग्निशमन विभाग और नागरिक प्रशासन की भूमिका की समीक्षा करेगी। कोलकाता नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और सीईएससी लिमिटेड सहित संबंधित एजेंसियों के कामकाज की भी पड़ताल की जाएगी। जांच दल यह देखेगा कि आयोजन के लिए आवश्यक अनुमतियां ली गई थी या नहीं, सुरक्षा योजना निर्धारित नियमों के अनुरूप तैयार की गई थी या नहीं और पुलिस बल तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं की तैनाती पर्याप्त थी या नहीं। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की स्थिति की भी जांच की जाएगी, क्योंकि बड़े आयोजनों में किसी की जानकारी किस समय मिली थी और संबंधित विभागों का एक-दूसरे के साथ तालमेल भी आवश्यक होता है।

पीएम-दक्ष योजना पर कांग्रेस का हमला, जयराम रमेश बोले- ‘झोला उठाने का वक्त आ गया’

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने पीएम-दक्ष योजना के क्रियान्वयन को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि वंचित वर्गों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी। उन्होंने दावा किया कि सरकार की ओर से योजना को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन इसके क्रियान्वयन में गंभीर कमियां सामने आई हैं। रमेश ने बजट के इस्तेमाल और योजना को लागू करने में कथित देरी का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर राजनीतिक हमला बोला और कहा कि अब सरकार के लिए ‘झोला उठाने का वक्त आ गया’ है। कांग्रेस के इन आरोपों ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, बजट के उपयोग और वंचित समुदायों तक उनके लाभ पहुंचाने को लेकर राजनीतिक बहस को फिर तेज कर दिया है।

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीएम-दक्ष योजना की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नाम से जुड़ी योजना के परिणाम उसके प्रचार और दावों के

अनु रूप दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार विज्ञापनों और सुविधियों के जरिए योजनाओं की उपलब्धियां गिाने पर अधिक जोर देती है, जबकि वास्तविक स्तर पर उनके क्रियान्वयन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उनके मुताबिक, यदि किसी योजना का उद्देश्य वंचित समुदायों के युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसरों से जोड़ना है, तो उसकी सफलता का आकलन केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों और उन्हें मिले रोजगार के अवसरों के आधार पर किया जाना चाहिए।

कांग्रेस ने विशेष रूप से योजना को दो साल के लिए निलंबित करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्षों में आवंटित बजट का पूरा इस्तेमाल नहीं होने के आरोपों को मुद्दा बनाया है। रमेश का कहना है कि बजट आवंटित होने के बावजूद यदि की प्रगति रिपोर्ट से स्पष्ट होगी। कांग्रेस ने इन कथित कमियों के आधार पर केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। पीएम-दक्ष योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लोगों को कौशल विकास तथा प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे रोजगार प्राप्त करने, स्वरोजगार शुरू करने या अपनी आजीविका बेहतर बनाने में सक्षम हो सकें। ऐसी योजनाओं का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि आर्थिक संसाधनों और प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी के कारण कई समुदायों के युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए उन्हें रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना और

आजीविका के अवसरों से जोड़ना सरकार की सामाजिक कल्याण संबंधी नीतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जयराम रमेश ने इसी उद्देश्य का हवाला देते हुए सरकार से सवाल किया कि जब योजना वंचित वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है, तो इसके क्रियान्वयन में कथित देरी क्यों हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना के नाम और प्रचार के मुकाबले जमीनी स्तर पर काम कम दिखाई देता है। कांग्रेस नेता के अनुसार, सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि योजना के लिए आवंटित राशि का कितना उपयोग हुआ, कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण के बाद कितने लाभार्थियों को रोजगार या स्वरोजगार के अवसर मिल सके। इन सवालों के जवाब से योजना की वास्तविक प्रगति और उसके प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने सरकार की जवाबदेही को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री के नाम पर शुरू की गई योजना कमी के कारण कई समुदायों के युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो सरकार को अपनी कार्यशैली पर विचार करना चाहिए। रमेश ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए दावा किया कि सरकार लोगों का भरोसा रही है और उसकी विदाई का समय करीब है।

चेन्नई में 27 वर्षीय फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर मृत मिला, पिता ने साइबर उत्पीड़न का लगाया आरोप

चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पास मुत्तुकाडु इलाके में एक किराए के विला से 27 वर्षीय फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर वी. हरीश का शव मिलने के बाद सोशल मीडिया पर कथित साइबर उत्पीड़न का मामला सामने आया है। हरीश सोशल मीडिया पर ‘फाइनेंस विद हरीश’ नाम से लोकप्रिय थे और वित्तीय विषयों तथा निवेश से जुड़ी सामग्री साझा करते थे। उनकी मौत के बाद उनके पिता ने एक यूट्यूबर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि ऑनलाइन वीडियो के जरिए हरीश की योग्यताओं पर सवाल उठाए गए, जिसके बाद उन्हें कथित तौर पर उत्पीड़न और दबाव का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मामले में अप्राकृतिक मृत्यु का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, हरीश मुत्तुकाडु के पास एक किराए के विला में मृत पाए गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की। इस मामले ने सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वाले लोगों की जिम्मेदारी, सार्वजनिक आलोचना की सीमा और ऑनलाइन व्यवहार से जुड़े सवालों को भी चर्चा में ला दिया है। हालांकि, फिलहाल यह स्थापित नहीं हुआ है कि हरीश की मौत का संबंध कथित ऑनलाइन उत्पीड़न से था या नहीं। पुलिस जांच के बाद ही घटनाक्रम की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। हरीश के पिता विनायगम ने कनाथूर पुलिस थाने में यूट्यूबर और ‘जेमुरिया इंक’ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेसन सैमुअल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सैमुअल ने 18 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें हरीश की वित्तीय सलाह देने की योग्यता



है या नहीं। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब सोशल मीडिया पर वित्तीय सलाह देने वाले कंटेंट क्रिएटर बड़ी संख्या में दर्शकों से प्रभावित किया और इसी के चलते उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि, यह पिता की ओर से लगाया गया आरोप है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले में जेसन सैमुअल ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर साइबर उत्पीड़न के आरोपों को खारिज किया है। उनका पक्ष सामने आने के बाद अब जांच में शिकायत में लगाए गए आरोपों, संबंधित वीडियो की सामग्री, उसके प्रकाशन के समय और उसके बाद हुए ऑनलाइन संवादों की पड़ताल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पुलिस को यह भी स्पष्ट करना होगा कि कथित उत्पीड़न के आरोपों के समर्थन में क्या साक्ष्य उपलब्ध हैं और उनका घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध है या नहीं। पुलिस ने फिलहाल अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

भुवनेश्वर। ओडिशा की राजनीति में बीजू जनता दल (बीजद) प्रमुख नवीन पटनायक के एक बयान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका की रिहाई की मांग का समर्थन करने पर भारतीय जनता पार्टी ने पटनायक पर तीखा हमला बोला है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पटनायक राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ऐसे मुद्दों को हवा दे रहे हैं, जिनसे देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा होने की आशंका को लेकर भ्रम फैल सकता है। सत्तारूढ़ भाजपा ने इस पूरे मामले को लोकतांत्रिक व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ते हुए बीजद प्रमुख की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। विवाद की शुरुआत दिल्ली में सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका को हिरासत में लिए जाने के बाद हुई। दोनों नेताओं को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर की ओर मार्च करने के दौरान हिरासत में लिया गया था। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई। नवीन पटनायक ने उनकी रिहाई की मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखना उचित नहीं है, भले ही ऐसा किसी

प्रतिबंधित क्षेत्र में किया गया हो। उनके इस बयान को भाजपा ने केवल हिरासत के मुद्दे तक सीमित नहीं माना, बल्कि इसे राजनीतिक संदेश देने और सरकार को कार्रवाई पर सवाल खड़े करने की कोशिश बताया। भाजपा नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध प्रदर्शन का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ कानून और सार्वजनिक व्यवस्था का पालन करना भी आवश्यक है। पार्टी ने दावा किया कि संबंधित अधिकारियों ने शांति भंग होने और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की थी। भाजपा प्रवक्ता अनिल बिस्वाल के अनुसार, कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दोनों सीजेपी नेताओं को 21 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। भाजपा का तर्क है कि जब किसी मामले में प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया चल रही हो, तब राजनीतिक बयानबाजी के जरिए उस पर दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। अनिल बिस्वाल ने नवीन पटनायक पर प्रचार हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए उनकी तुलना कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी की। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां कानून और संस्थाओं की अपनी भूमिका

है। उनके अनुसार, लोकतंत्र और भीड़तंत्र के बीच अंतर को समझना जरूरी है। भाजपा ने पटनायक के बयान को इसी संदर्भ में उठाते हुए आरोप लगाया कि वह राजनीतिक समर्थन खड़े करने की कोशिश बताया। भाजपा नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध प्रदर्शन का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ कानून और सार्वजनिक व्यवस्था का पालन करना भी आवश्यक है। पार्टी ने दावा किया कि संबंधित अधिकारियों ने शांति भंग होने और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की थी। भाजपा प्रवक्ता अनिल बिस्वाल के अनुसार, कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दोनों सीजेपी नेताओं को 21 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। भाजपा का तर्क है कि जब किसी मामले में प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया चल रही हो, तब राजनीतिक बयानबाजी के जरिए उस पर दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। अनिल बिस्वाल ने नवीन पटनायक पर प्रचार हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए उनकी तुलना कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी की। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां कानून और संस्थाओं की अपनी भूमिका

मतदाता बनाने देने या मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विरोध करने संबंधी आरोप भाजपा ने लगाए हैं। इन दावों की पुष्टि के लिए संबंधित दस्तावेजों, आधिकारिक आंकड़ों और दोनों पक्षों के विस्तृत पक्ष को देखना आवश्यक होगा। मतदाता सूची में नाम शामिल करने और हटाने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत चलाई जाती है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल पर लगाए गए आरोपों का आकलन तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर किया जाना जरूरी है। भाजपा ने पटनायक की टिप्पणी को राजनीतिक अवसरवाद से जोड़ते हुए सवाल उठाया कि क्या विपक्षी दलों को केवल भाजपा ने बीजद प्रमुख पर आरोप लगाया कि वह राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के बसने, उनके मतदाता बनने और मतदाता सूची की जांच से जुड़े सवालों पर पर्याप्त सख्त रुख नहीं अपना रहे हैं। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि पटनायक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं। भाजपा का दावा है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक दलों को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए, ताकि मतदाता सूची की शुद्धता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। हालांकि, अवैध प्रवासियों को बसाने, उन्हें



नवसर्जन संस्कृति

हिन्दी



JioTV

CHENNAL NO. 2063



Jio Air Fiber



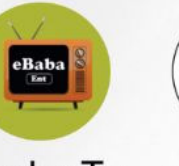
Jio Tv +



Jio Fiber



Daily Hunt



ebaba Tv



Dish Plus



DTH live OTT



Rock TV



Airtel



Amezone Fire



Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये



संपादकीय

तलाशें उबाल से उपजे सवालॉ के निहितार्थ

फ्रांस में स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन धीरे-धीरे आगजनी और मौल व महंगे स्टोरो में लूट तक जा पहुंचा है। निस्संदेह, कथित वैश्वीकरण और उदारीकरण के चलते वैश्विक स्तर पर उपजी आर्थिक विषमता ने अमीरी-गरीबी की खाई को और गहरा किया है। एक ओर जहां व्यापार के केंद्र बने अभिजात्य वर्ग के स्कूल-कॉलेज व विश्वविद्यालय फल-फूल रहे हैं,वहीं सरकारी अनुदान से चलने वाले शिक्षण संस्थानों की बदहाली जगजाहिर है। यह विषमता विषमव्यापी है और आक्रोश भी। दरअसल, लोकांत्रिक सरकारों की जो परंपरागत कल्याणकारी नीतियों की अवधारणा थी, वह नये आर्थिक दौर में मुनाफे पर आधारित व्यवस्था में तब्दील होती गई। राजनेताओं व सत्ता से जुड़े लोगों की शैक्षणिक संस्थाओं के मुनाफे में भागीदारी ने स्थितियों को विषम बनाया है। हालाँकि, सत्ताधीशों की विलासिता में कोई कमी नहीं आई, लेकिन आम जनता चौरफाटा आर्थिक दबावों से जूझ रही है। सबसे पहले एक सदी बाद आई कोरोना की महामारी ने विश्व आपूर्ति श्रृंखला को तो बाधित किया ही, सैकड़ों किस्म के रोजगारों को भी खत्म किया। जैसे-तैसे एक साल बाद उस आर्थिक संकट से दुनिया उबरने की कोशिश में थी कि युद्ध ने सब चौपट कर दिया। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को पहले रूस-यूक्रेन युद्ध ने बुरी तरह प्रभावित किया। फिर इस्त्राएल-हमास संघर्ष ने इस संकट को बढ़ाया। इसके उपरांत अमेरिका द्वारा ईरान पर थोपे गये युद्ध ने पूरी दुनिया में ईंधन संकट खड़ा कर दिया। दुनिया के देशों के बजट चरमराए और लोक कल्याण से जुड़ी संस्थाएं और योजनाएं हाशिये पर आ गईं। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने से ईंधन के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और महंगाई कूलने परने लगी। जो कालांतर सामाजिक अस्तंशों की वाहक बनी। निस्संदेह, सुनहरे सपने लेकर आगे बढ़ रही युवा पीढ़ी की आशाओं पर इस संकट ने तुषारापात किया। शिक्षा व्यवस्था महंगी हुई और रोजगार के अवसर सिमटते गए। निस्संदेह, दुनिया की महाशक्तियों की निरंकुश व निर्भम नीतियों ने पूरी दुनिया में लोगों के जीवन को कष्टकारी बनाया है। इसीलिए भविष्य की आशांकाओं ने युवाओं को आक्रोशित किया।

दरअसल, यूरोप के जिन तमाम देशों में फिलहाल आक्रोश की लपेट दिखायी दे रही हैं, उनके मूल में सिर्फ युवाओं का गुस्सा ही नहीं है। इस तपिश में रोटी संकने के लिये राजनीतिक दल आतुर दिखायी देते हैं। फ्रांस में जहां दक्षिणपंथी उभार के संगेत दिखायी दे रहे हैं, वहीं कुछ देशों में वाम व श्रमिक संघटन अपने अवसर तलाश रहे हैं। जहां दक्षिणपंथी दल प्रवासियों को अपने-अपने देश की समस्याओं की वजह बता रहे हैं, वहीं वामपंथी दल सत्ता में भागीदारी को आतुर हैं। यह कटु सत्य यह है कि जिन देशों में इस समय आंदोलन उभार पर हैं, उनमें से स्पेन, फ्रांस, इटली,पोलैंड और ग्रीस में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। अतः इन आंदोलनों के राजनीतिक निहितार्थ समझना कठिन नहीं होगा। आम आदमी जहां पेट्रोलियम पदार्थों, खाद्य वस्तुओं की कीमतें और आवासीय महंगाई बढ़ने से आक्रोशित है, वहीं युवा रोजगार संकट से त्रस्त हैं। उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय दिखायी दे रहा है। वहीं अल्बानिया में हिंसक रूप ले चुका आंदोलन सिस्टम के भ्रष्टाचार के निरुद्ध मुखर है। आंदोलनकारियों ने लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभों से जुड़े संस्थानों तक को आग के हवाले किया है। दरअसल, समाज में एक ओर अभिजात्य वर्ग की विलासिता बढस्तर जारी है, वहीं दूसरी ओर समाज के एक बड़े वर्ग को रोटी-कपड़ा-मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है। सत्ताधीशों की संवेदनहीनता और लोक कल्याण के वायदों का हकीकत न बन पाना आक्रोश की वजह बन रहा है। कहीं न कहीं कथित सोशल मीडिया में भी इस तपिश को ईंधन उपलब्ध कराया है। जिसमें दिखाया जा रहा स्वनलोक तो तुभावना है, लेकिन हकीकत खुरदरी है। एक तरफ अथाह विलासिता के बिंब हैं, दूसरी तरफ जीवन की मूलभूत जरूरतों का संकट। वहीं सोशल मीडिया पर प्रसारित अप्रामाणिक व अतिरंजित सामग्री युवाओं को आक्रामक बना रही है। वे विषमता व निसंगतियों के खिलाफ खड़े होते हैं तो उनका आंदोलन निहित स्वार्थी तर्कों द्वारा हेक कर लिया जाता है। निस्संदेह, दुकानों को लूटने वाले जेन-जी नहीं हो सकते। मांसक व हूडी पहनकर सुपर बाजार व मॉल लूटने वालों की वास्तविक पहचान करने की जरूरत है।

अभियान

भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा में ऐसे अनेक मंदिर हैं, जिनकी विशेषताएं श्रद्धालुओं को आश्चर्यचकित करने के साथ-साथ आध्यात्मिक संदेश भी देती हैं। कहीं भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में आधे पुरुष और आधी नारी के स्वरूप में दर्शन देते हैं, तो कहीं भगवान विष्णु और शिव की संयुक्त आराधना की परंपरा देखने को मिलती है। इसी अद्भुत धार्मिक विरासत के बीच तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित मध्य कैलाश मंदिर अपनी अनेखी प्रतिमा के कारण विशेष पहचान रखता है। यहां भगवान गणेश और हनुमान जी एक संयुक्त स्वरूप में विराजमान हैं, जिन्हें आद्यंत प्रभु के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा में भगवान गणेश का स्वरूप दाईं ओर और भगवान हनुमान का स्वरूप बाईं ओर दिखाई देता है। दो अलग-अलग देवताओं के गुणों और प्रतीकों को एक ही विग्रह में समाहित करने वाली यह प्रतिमा भक्तों के लिए श्रद्धा, जित्नास और आध्यात्मिक चिंतन का केंद्र है। चेन्नई के दक्षिण हिस्से में स्थित मध्य कैलाश मंदिर को स्थानीय स्तर पर नाटुक्कीपिलाई के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर शहर की धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां भगवान शिव सहित अनेक देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की जाती है। हालाँकि मंदिर की प्रसिद्धि एक बड़ा कारण आद्यंत प्रभु का अनूठा स्वरूप है। सामान्यतः भगवान

आस्था के सैलाब में कब तक गुम होती रहेगी जिंदगियां?

“साथ ही यह मान लेना भी उचित नहीं कि हर भगदड़ का कारण केवल प्रशासनिक विफलता है। कई बार अफवाह, धक्का-मुक्ती, अचानक आगे बढ़ने की प्रवृति और दूसरों की सुरक्षा की चिंता किए बिना स्वयं निकलने की कोशिश भी स्थिति को भयावह बना देती है। इसलिए आम नागरिकों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है।

प्रेरणा

सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा हमेशा कठिन परिस्थितियां नहीं होतीं, बल्कि कई बार हमारा अपना भटकता हुआ मन होता है। मनुष्य के पास प्रतिभा हो, ज्ञान हो और आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा भी हो, फिर भी यदि वह अपने विचारों को एक दिशा में केंद्रित नहीं कर पाता, तो उसकी क्षमताएं बिखरकर रह जाती हैं। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखता है और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को विचलित नहीं होने देता, वह सीमित साधनों के बावजूद बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। एकाग्रता ऐसी ही आंतरिक शक्ति है, जो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने की प्रेरणा देती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ा एक चर्चित प्रेरक प्रसंग इसी गुण की महत्ता को उभारकर करता है। सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व साहस, आत्मविश्वास, अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक रहा है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक ऐसे निर्णय लिए, जिनके लिए असाधारण मानसिक मजबूती की आवश्यकता थी। देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले इस महान सेनानी ने युवावस्था में ही अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया था। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां बताती हैं कि वह केवल विचारों से ही दृढ़ नहीं थे, बल्कि अध्ययन, तर्क और बौद्धिक क्षमता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योग्यता रखते थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि किसी व्यक्ति की वास्तविक शक्ति केवल उसकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के बीच उसके व्यवहार और निर्णयों से पहचानी जाती है।

जहां गणेश और हनुमान एक रूप में देते हैं दर्शन, चेन्नई के मध्य कैलाश मंदिर में विराजते हैं आद्यंत प्रभु

गणेश की पूजा बुद्धि, विवेक, शुभारंभ और विघ्नों को दूर करने वाले देवता के रूप में की जाती है, जबकि भगवान हनुमान शक्ति, भक्ति, साहस, सेवा और समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं। इन दोनों देवताओं का संयुक्त स्वरूप भक्तों को यह संदेश देता है कि जीवन में बुद्धि और शक्ति का संतुलन होना आवश्यक है। केवल समर्थन प्योपन नहीं है, उसे विवेक के साथ इस्तेमाल करना भी जरूरी है। इसी प्रकार ज्ञान तभी सार्थक होता है, जब उसके साथ साहस, कर्म और निष्ठा जुड़ी हों।

मध्य कैलाश मंदिर में विराजमान आद्यंत प्रभु की प्रतिमा अपनी बनावट और धार्मिक अवधारणा के कारण विशेष मानी जाती है। प्रतिमा के दाहिने भाग में भगवान गणेश और बाएं भाग में भगवान हनुमान के स्वरूप का समावेश है। इस संयुक्त रूप को देखकर श्रद्धालुओं के मन में सहज ही यह प्रश्न उठता है कि दो अलग-अलग देवताओं को जित्नास और आध्यात्मिक चिंतन का केंद्र है। चेन्नई के दक्षिण हिस्से में स्थित मध्य कैलाश मंदिर को स्थानीय स्तर पर नाटुक्कीपिलाई के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर शहर की धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां भगवान शिव सहित अनेक देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की जाती है। हालाँकि मंदिर की प्रसिद्धि एक बड़ा कारण आद्यंत प्रभु का अनूठा स्वरूप है। सामान्यतः भगवान

कथा का विशेष स्थान है।

आद्यंत प्रभु का नाम भी अपने भीतर गहरा आध्यात्मिक अर्थ समेटे हुए है। ‘आद्यंत’ शब्द का आशय आदि और अंत से है। आद्यंत प्रभु को ऐसे दिव्य स्वरूप के रूप में देखा जाता है, जो शुरुआत और समाप्ति के सीमाओं से परे हैं। हिंदू दर्शन में परम सत्ता को अनेक बार आनादि और अंतत कहा गया है। इसका अर्थ है कि ईश्वर का अस्तित्व किसी सामान्य मानवीय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। सृष्टि में सत्ता, विकास और परिवर्तन का क्रम निरंतर चलता रहता है, लेकिन परम तत्व को इन सीमाओं से परे माना जाता है। इस दृष्टि से आद्यंत प्रभु का नाम श्रद्धालुओं को जीवन की नश्वरता और आध्यात्मिक सत्ता की व्यापकता पर विचार करने का अवसर देता है। भगवान गणेश और हनुमान जी का संयुक्त स्वरूप अपने आप में कई धार्मिक प्रतीकों को समाहित करता है। गणेश जी को भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र माना जाता है। उनके गम्भीर स्वरूप के पीछे त्याग, पुनर्जन्म, बुद्धि और विघ्नों पर विजय की कथा जुड़ी है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में गणेश जी का स्मरण करने की परंपरा इसी विश्वास से संबंधित है कि उनके आशीर्वाद से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। दूसरी ओर, भगवान हनुमान को

भगवान श्रीराम का परम भक्त माना जाता है। रामायण में उनकी निष्ठा, अदम्य साहस, बुद्धिमत्ता और सेवाभाव का विशेष वर्णन मिलता है। समुद्र पार करके लंका पहुंचना, माता सीता का पता लगाना और संकट के समय संजीवनी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाने जैसे प्रसंग उनकी असाधारण क्षमता को बता रही जाती हैं। आज भी भक्त इस अनोखे विग्रह के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा-अर्चना करते हैं। मंदिर में पूजा की विधियां भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का विषय हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार, आद्यंत प्रभु की आरती में कण्ठ जलाया जाता है। कण्ठ की लौ को हिंदू पूजा-पद्धति में पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। कण्ठ जलने के बाद स्वयं समाप्त हो जाता है और वातावरण में सुगंध छोड़ता है। आध्यात्मिक व्याख्या में इसे अहंकार त्यागकर ईश्वर के प्रति समर्पित होने के भाव से जोड़ा जाता है। मंदिर से जुड़ी जानकारियों के अनुसार, दोपहर में पुनारी प्रतिमा का स्नान कराते हैं और इसके बाद गीले वस्त्रों में ही अनुष्ठान आरंभ करते हैं। मध्य कैलाश मंदिर में आद्यंत प्रभु की प्रतिमा का कुंभाभिषेक वर्ष 1994 में सम्पन्न हुआ था। दक्षिण भारतीय मंदिर परंपरा में कुंभाभिषेक एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। इसके अतिरंत मंदिर और देवप्रतिमा से संबंधित वैदिक तथा आगमिक विधियों के अनुसार

विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। इस अवसर पर मंदिर की आध्यात्मिक प्रतिष्ठा और धार्मिक परंपरा को नए सिर से अभिव्यक्त किया जाता है। मध्य कैलाश में इस अनुष्ठान के बाद आद्यंत प्रभु की प्रतिमा को लेकर श्रद्धालुओं की रफ्त और पहचान बढ़ने की बात कही जाती है। आज भी भक्त इस अनोखे विग्रह के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा-अर्चना करते हैं। मंदिर में पूजा की विधियां भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का विषय हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार, आद्यंत प्रभु की आरती में कण्ठ जलाया जाता है। कण्ठ की लौ को हिंदू पूजा-पद्धति में पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। कण्ठ जलने के बाद स्वयं समाप्त हो जाता है और वातावरण में सुगंध छोड़ता है। आध्यात्मिक व्याख्या में इसे अहंकार त्यागकर ईश्वर के प्रति समर्पित होने के भाव से जोड़ा जाता है। मंदिर से जुड़ी जानकारियों के अनुसार, दोपहर में पुनारी प्रतिमा का स्नान कराते हैं और इसके बाद गीले वस्त्रों में ही अनुष्ठान आरंभ करते हैं। यह विशेष पूजा-परंपरा मंदिर की धार्मिक विशेषताओं में गिनी जाती है। पूजा-विधि में समय के साथ स्थानीय परंपराओं और निर्धारित धार्मिक नियमों का महत्व बना रहता है।

मध्य कैलाश मंदिर की विशेषता केवल

आद्यंत प्रभु की प्रतिमा तक सीमित नहीं है। यहां भगवान शिव मुख्य देवताओं में शामिल हैं। इसके अलावा वेंकट आनंद विनायक, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य की भी आराधना की जाती है। अलग-अलग देवताओं के मंदिरों की उपस्थिति हिंदू धर्म की व्यापक उपासना परंपरा को दर्शाती है। भगवान शिव को सृष्टि के परिवर्तन और संहार से संबंधित दिव्य सत्ता के रूप में पूजा जाता है। भगवान विष्णु को पालनकर्ता माना जाता है, जबकि सूर्यदेव जीवन, प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत के रूप में पूजनीय हैं। गणेश जी की उपासना शुभारंभ और बुद्धि से जुड़ी है। इस प्रकार मंदिर का धार्मिक वातावरण विभिन्न आध्यात्मिक अवधारणाओं और उपासना-पद्धतियों को एक स्थान पर प्रस्तुत करता है।

चेन्नई जैसे महानगर में स्थित यह मंदिर आधुनिक जीवन की व्यस्तता के बीच श्रद्धालुओं को धार्मिक आस्था से जुड़ने का अवसर देता है। मंदिरों का महत्व केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे समाज की सांस्कृतिक स्मृति, परंपराओं और सामूहिक विश्वासों की भी संजोते हैं। पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही कथाएं और भगवान लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं। मध्य कैलाश मंदिर का आद्यंत प्रभु स्वरूप भी इसी धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा का विशिष्ट उदाहरण है।

इस पुरे परिदृश्य में प्रशासन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। पुलिस और स्थानीय शासन को केवल अनुमति जारी करने अथवा आयोजन के दौरान औपचारिक निरीक्षण करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अनुमति से पहले स्थल का निरीक्षण, भीड़ की संभावित संख्या का आकलन, सुरक्षा मानकों की जांच और निकास मार्गों की उपलब्धता का सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए। निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश देने पर तत्काल रोक लगाई जाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले आयोजकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो और यदि जांच में अधिकारियों की लापरवाही सामने आए, तो उनकी जवाबदेही भी तय की जाए। किसी समिति का प्रभाव, किसी आयोजक की प्रतिष्ठा या किसी उत्सव की निरीक्षण, भीड़ की संभावित संख्या का आकलन, सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच हजारों लोगों को प्रवेश देना उत्सव की सफलता नहीं, बल्कि एक संभावित त्रासदी को आमंत्रण देना है। कोलकाता की घटना ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भीड़ प्रबंधन कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन रक्षा की अनिवार्य व्यवस्था है। किसी भी बड़े धार्मिक आयोजन से पहले स्थल की क्षमता का वैज्ञानिक आकलन होना चाहिए। प्रवेश और निकास के रास्ते अलग-अलग तथा पर्याप्त चौड़े होने, आपातकालीन निकास स्पष्ट रूप से चिह्नित हों, भीड़ की आवाजाही एक दिशा में नियंत्रित की जाए और प्रशिक्षित कर्मियों की पर्याप्त तैनाती हो। सीसीटीवी, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, चिकित्सा सहायता, एंबुलेंस तथा अग्निशमन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बारिश, बिजली बाधित होने, अचानक अफवाह फैलने या किसी अत्यावृथाित घोषणा से भीड़ का व्यवहार बदल सकता है। इसलिए हर आयोजन में आपातकालीन योजना, नियमित अभ्यास और त्वरित प्रतिक्रिया की व्यवस्था होनी चाहिए। सुरक्षा की तैयारी हादसे के बाद नहीं, आयोजन की योजना बनाते समय शुरू होनी चाहिए।

अनदेखी होती है, तो वह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि उन मूल्यों से विचलन भी है, जिनका उत्सव मनाने का दावा किया जाता है। देवी की आराधना करने वाले समाज को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी श्रद्धालु की जान अव्यवस्था के कारण न जाए। श्रद्धा का अर्थ आंखें बंद करके भीड़ का हिस्सा बन जाना नहीं, बल्कि विवेक, संयम और जिम्मेदारी के साथ अपने धर्म का निर्वह करना है।

अब समय आ गया है कि हर ऐसी त्रासदी को एक स्वतंत्र जांच, स्पष्ट जवाबदेही और ठोस सुधारों से जोड़ा जाए। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो, दोषियों पर समयबद्ध कार्रवाई हो और भविष्य के आयोजनों के लिए लागू किए जाने वाले सुरक्षा मानकों की नियमित समीक्षा हो। श्रद्धे और राज्य सरकारों को बड़े धार्मिक आयोजनों के लिए एक समान न्यूनतम सुरक्षा मानक विकसित करने चाहिए। आयोजक समितियों, प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य सेवाओं और स्वयंसेवकों के बीच समन्वय को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इन व्यवस्थाओं का पालन केवल कागजों में नहीं, जमीन पर दिखाई देना चाहिए। कोलकाता की त्रासदी हमें चेतावनी दे रही है कि उत्सव की चमक के पीछे छिपी लापरवाही कभी भी अंधकार बनकर उतर सकती है। मृतकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि केवल शोक व्यक्त करना या उनके परिवर्जनों को सहायता देना नहीं, बल्कि यह संकल्प लेना है कि ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा न हों। सरकार जागे, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझे, आयोजक अपनी प्रतिष्ठा से पहले लोगों की सुरक्षा को रखें और नागरिक अपनी आस्था के साथ विवेक को भी स्थान दें। आखिर कितने हादसों के बाद हम सोचेंगे? कितने परिवारों के उड़नने के बाद हमारी व्यवस्थाएं बदलेंगी? और कितनी जिंदगियों की कीमत पर हम समझेंगे कि कोई भी उत्सव, कोई भी आयोजन और कोई भी धार्मिक आस्था मनुष्य के जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। आस्था का सच्चा सम्मान तभी होगा, जब हर श्रद्धालु उत्सव में सुरक्षित प्रवेश करे और संकुशल अपने घर लौटे।

दशहरा रैली में उद्धव और शिंदे की ताजा भिड़ंत ने बालासाहेब की विरासत की जंग को और भड़का दिया है

महाराष्ट्र की राजनीति में दशहरा पर्व सियासी शक्ति प्रदर्शन और एक-दूसरे पर हमले का बड़ा मौका भी है। मुंबई में इस बार भी यही नजारा दिखा। दादर के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की हुंकार थी, तो भोरेगंव के नरेंको सेंटर में एकनाथ शिंदे का पलटवार था। दोनों नेता एक-दूसरे पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी असली नजर महाराष्ट्र की जनता पर थी, जिसे तय करना है कि बालासाहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत का असली वारिस कौन है। शिंदे को उनके ही पुराने फैसलों के कठपुतरे में खड़ा करने की कोशिश है। उनका तर्क था कि 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़कर बाद में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाना मतदाताओं के जनशक्ति के साथ विवादास्पद था। शिंदे ने इसे ही सबसे बड़ी ‘वोट चोरी’ करार दिया। देखा जाये तो यह एकनाथ शिंदे की सियासत का केंद्रीय तर्क है। वह उद्धव को याद दिलाना चाहते हैं कि सत्ता की राजनीति में नैतिकता का सवाल उठाने से पहले अपने पुराने फैसलों का हिसाब भी देना पड़ता है। उनसे लिए 2022 में शिवसेना से बग़ावत करना पार्टी को बचाने की लड़ाई है, जबकि उद्धव के लिए वही घटना पार्टी तोड़ने और जनशेरा की अवमानना का उदाहरण है। यानि एक ही घटना, परन्तु अभिमान से जोड़ना चाहते हैं, वहीं शिंदे सत्ता कि शिवसेना को तोड़ा गया, शिंदे कहते हैं कि खिलाफ विपक्ष की वेबेनी बलकर खारिज करना चाहते हैं।साथ ही उद्धव और शिंदे की दशहरा रैली से जो तस्वीर उभरती है वह साफ बताती है कि यह मुकाबला अब मजद दो नेताओं की निजी अदवात नहीं रह गया है। इसके केंद्र में हिंदुत्व की परिभाषा, मराठी अस्मिता, किसानों की बदहाली, चुनावी जनशेरा और सत्ता की वैधता जैसे सवाल हैं। दोनों खेमे अपनी-अपनी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा जनता की अदवात में होती है। देखा जाये तो शिवाजी पार्क उद्धव ठाकरे के लिए सिर्फ रैली का मैदान नहीं, राजनीतिक के वोटों से? हम आगेको यह भी बता दें कि इस बार बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना की आक्रामक की राजनीति को आवाज दी थी। उद्धव इसी विरासत को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका संदेश था कि शिवसेना की पहचान किसी भी प्रकार के फैसले, किसी सरकारो मुहर या सत्ता के गणित से तय नहीं होगी। उद्धव ने भाजपा के साथ अपने पुराने गठबंधन को बड़ी राजनीतिक पहचान से समझौता किसेन किया। उद्धव ने मतदाता सूची से वकीत रूप से नाम हटाए जाने, संवैधानिक संस्थाओं और केन्द्र की कार्यशील को लेकर भी सवाल उठाए। युवा प्रदर्शनकारियों को उन्होंने अराजक तत्व नहीं, बल्कि बदलाव की मांग करने वाले ग़ौरव माने। प्रथनमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व पर निशाना

पंजाब में तीन लाख सरकारी कर्मचारी दो दिन की हड़ताल पर, दफ्तरों से लेकर बस सेवाओं तक असर की आशंका

चंडीगढ़। पंजाब में अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। राज्य के करीब तीन लाख सरकारी कर्मचारी बुधवार से दो दिन के सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर चले गए हैं। कर्मचारियों की संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) ने राज्य सरकार के खिलाफ दो दिवसीय आंदोलन का ऐलान किया है। कर्मचारियों के इस फैसले से सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। वहीं, रोडवेज कर्मचारी संगठनों के समर्थन के कारण बस सेवाओं पर भी असर पड़ने की संभावना जताई गई है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगें लंबित हैं, लेकिन सरकार की ओर से ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसी नाराजगी के चलते संगठनों ने सामूहिक अवकाश लेकर सरकार पर दबाव बनाने का फैसला किया है। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक, आंदोलन का उद्देश्य सरकार का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करना है, जिन पर लंबे समय से चर्चा होती रही है, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में महंगाई भत्ते (डीए) के लंबित 18 फीसदी बकाये का भुगतान, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली,

वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करना और सेवा शर्तों को प्रभावित करने वाले सरकारी आदेशों को वापस लेना शामिल है। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी आंदोलन का अहम हिस्सा है। संगठनों का कहना है कि इन मांगों का सीधा संबंध कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा, भविष्य और सेवा संबंधी अधिकारों से है। 'साझा मुलाजिम मंच' के संयोजक सुखचैन खेड़ा ने बताया कि कर्मचारी संगठनों को राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव के साथ बैठक करने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन संगठनों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ बैठक करने का वादा किया था, लेकिन ऐसी कोई बैठक नहीं हुई और कर्मचारियों की मांगों पर भी निर्णय नहीं लिया गया। कर्मचारी प्रतिनिधियों का कहना है कि केवल बैठक का प्रस्ताव मिलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार को लंबित मांगों पर स्पष्ट समयसीमा के साथ ठोस कदम उठाने चाहिए। कर्मचारियों के आंदोलन के पीछे महंगाई भत्ते का बकाया एक प्रमुख मुद्दा है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि लंबित 18 फीसदी डीए का भुगतान किया जाए, ताकि बढ़ती



महंगाई के बीच उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग भी लंबे समय से उठाई जा रही है। कर्मचारी संगठनों का

तर्क है कि पेंशन से जुड़ी व्यवस्था उनके सेवानिवृत्त जीवन की आर्थिक सुरक्षा से फ़िर से लागू करने की मांग भी लंबे समय से उठाई जा रही है। कर्मचारी संगठनों का

वापस लेने की मांग भी इसी आंदोलन का हिस्सा है। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का मुद्दा भी आंदोलन को व्यापक बना रहा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है

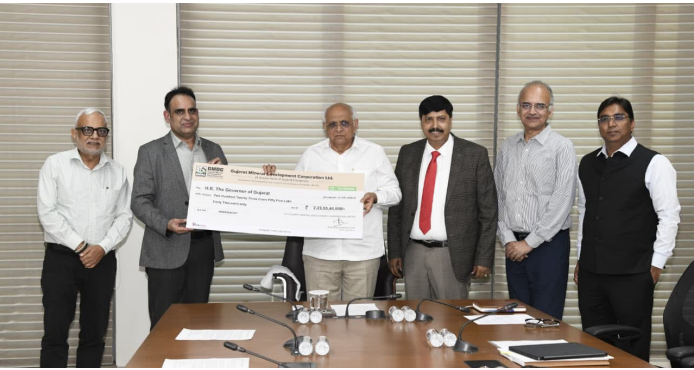
कि लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी सेवा का लाभ मिलना चाहिए। नियमितीकरण की मांग को लेकर कर्मचारियों में असंतोष बना हुआ है। संगठनों

का मानना है कि सरकार को इस विषय पर स्पष्ट नीति बनाकर कर्मचारियों की स्थिति का समाधान करना चाहिए। हालांकि, इन मांगों पर सरकार की ओर से अंतिम निर्णय की स्थिति और प्रत्येक मांग के क्रियान्वयन की समयसीमा स्पष्ट होना अभी बाकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच सितंबर में हुई बैठक के बाद भी आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। उस समय सरकार की ओर से कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर आश्वासन दिए जाने के बाद पहले चल रहे काम बंद आंदोलन को वापस ले लिया गया था। लेकिन इस फैसले से कर्मचारी संगठनों के कुछ सदस्यों में नाराजगी पैदा हो गई। उनका मानना था कि सरकार ने उनकी किसी भी प्रमुख मांग को स्वीकार नहीं किया और केवल आश्वासन के आधार पर आंदोलन वापस लेना उचित नहीं था। इसके बाद कर्मचारी संगठनों के भीतर दोबारा आंदोलन करने की मांग तेज हुई और अब सामूहिक आकस्मिक अवकाश के जरिए विरोध दर्ज कराया जा रहा है। दो दिवसीय आंदोलन के दौरान सरकारी कार्यालयों में नियमित कामकाज पर असर पड़ सकता है। कर्मचारियों की अनुपस्थिति से विभिन्न विभागों में लोगों को अपने जरूरी

काम कराने में परेशानी होने की आशंका है। रोडवेज कर्मचारी संगठनों के समर्थन के कारण सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, बस सेवाओं पर असर की वास्तविक स्थिति संबंधित कर्मचारी संगठनों की भागीदारी और संचालन व्यवस्था पर निर्भर करेगी। ऐसे में आम लोगों को सरकारी सेवाओं और परिवहन से जुड़े कार्यों के लिए स्थिति की जानकारी लेकर ही निकलने की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल पंजाब सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच गतिरोध बना हुआ है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि उनकी लंबित मांगों पर ठोस फैसला लिया जाए, जबकि आंदोलन के समाधान के लिए सरकार की ओर से आगे की बातचीत और निर्णय महत्वपूर्ण होंगे। दो दिन के सामूहिक अवकाश के बाद आंदोलन किस दिशा में जाएगा, यह सरकार की प्रतिक्रिया और कर्मचारियों के साथ संबंधित वार्ता पर निर्भर करेगा। यदि दोनों पक्षों के बीच सहमति बनती है तो कर्मचारियों की मांगों पर समाधान की राह निकल सकती है, लेकिन फिलहाल राज्य में कर्मचारी आंदोलन के कारण सरकारी कामकाज और बस सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर नजर बनी हुई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को जीएमडीसी द्वारा वर्ष 2025 26 के 223 करोड़ रुपए के डिविडेंड का चेक अर्पित किया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को गांधीनगर में बुधवार को देश की सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी खनन कंपनियों में से एक गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वर्ष 2025-26 के 223.54 करोड़ रुपए के डिविडेंड का चेक अर्पित किया गया। जीएमडीसी की स्थापना 1963 में हुई है और राज्य सरकार का यह उपक्रम खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक, कुशल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा राज्य के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जीएमडीसी मुख्य रूप से लिग्नाइट, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, फ्लोरस्पायर



और सिलिका सैंड सहित खनिजों के खनन और बिक्री से जुड़ी है। गुजरात के बाहर ओडिशा राज्य में बैतरानी वेस्ट, बुरापहार और कुदानाली-लुवरी नामक 3 कोयला

ब्लॉकों प्राप्त किए हैं। इससे गुजरात की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने में जीएमडीसी योगदान देगी। जीएमडीसी नवीकरणीय ऊर्जा

क्षेत्र में भी कार्यरत है तथा रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तांबा और अन्य रणनीतिक खनिजों के क्षेत्रों में विकास के अवसरों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री को जीएमडीसी के डिविडेंड की राशि में राज्य सरकार के हिस्से का यह चेक कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य सचिव श्री एम.के. दास ने अर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अडिया, जीएमडीसी के प्रबंध निदेशक श्री अजय भाट्ट, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार तथा अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रान्त पांडे उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल श्री संजय वात्स्यायन ने की शिष्टाचार भेंट

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से बुधवार को भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल श्री संजय वात्स्यायन ने गांधीनगर में शिष्टाचार भेंट की। वाइस एडमिरल श्री संजय वात्स्यायन ने मई-2026 से भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान के 35वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। मुख्यमंत्री के साथ इस शिष्टाचार भेंट में उन्होंने गुजरात के रणनीतिक समुद्री तट की सुरक्षा के संबंध में भारतीय नौसेना की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। श्री संजय वात्स्यायन वर्ष 1988 से भारतीय नौसेना में सेवारत हैं और अपने



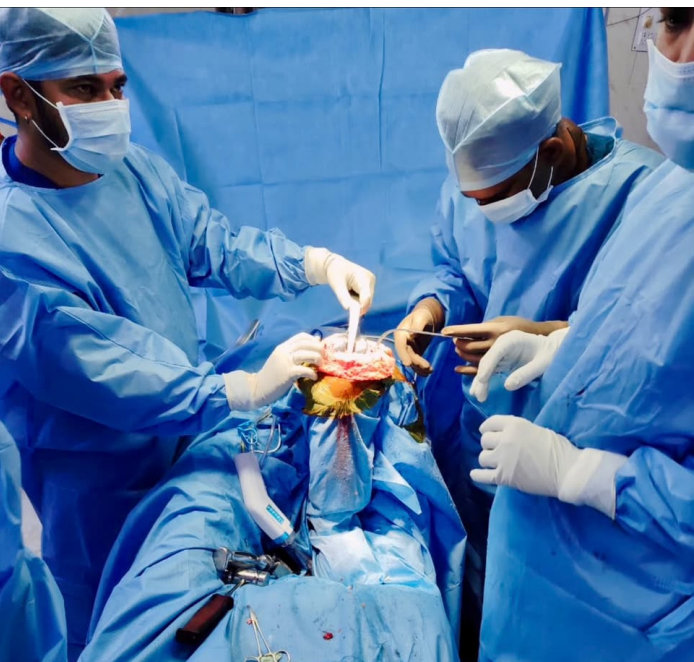
सेवाकाल के दौरान उन्होंने कई प्रमुख युद्धपोतों पर सेवाएँ दी हैं। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का पदभार संभालने

से पहले वे नौसेना मुख्यालय में वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी नौसेना

कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के नेतृत्व में संपूर्ण अरब सागर, पश्चिमी हिंद महासागर, होर्मुज स्ट्रेट, बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट और स्वेज नहर, मोजांबिक चैनल और केप ऑफ गुड होप जैसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट्स शामिल हैं। इना ही नहीं; देश के महत्वपूर्ण पश्चिमी समुद्री तट की रक्षा, व्यापार और ऊर्जा मार्गों को सुरक्षित करने तथा भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने में भी पश्चिमी नौसेना कमान की प्राथमिक भूमिका है। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल श्री संजय वात्स्यायन ने स्मृति चिह्न भी भेंट किया।

गांधीधाम रेलवे अस्पताल में वर्ष 2026 का चौथा सफल घुटना प्रत्यारोपण (नी रिप्लेसमेंट) ऑपरेशन

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के अंतर्गत गांधीधाम उपमंडलीय रेलवे अस्पताल में 19 अक्टूबर 2026 को 66 वर्षीय पुरुष रेलवे लाभार्थी का घुटना प्रत्यारोपण ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। मरीज घुटने में तेज दर्द और चलने-फिरने में परेशानी से पीड़ित थे। उनका ऑपरेशन अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. पार्थ राठी एवं एनेस्थेतिस्ट डॉ. हितेश शाह द्वारा अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में किया गया। इस ऑपरेशन में घुटने के खराब जोड़ को कृत्रिम जोड़ से बदला जाता है, जिससे मरीज को चलने-फिरने में राहत मिलती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026 में गांधीधाम रेलवे अस्पताल में अब तक घुटना प्रत्यारोपण के चार सफल ऑपरेशन किए जा चुके हैं। अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से रेलवे लाभार्थियों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा सेवाएँ मिल रही हैं। इससे इलाज के लिए दूर के अस्पतालों में जाने की जरूरत कम होती है और मरीजों एवं



उनके परिजनों को होने वाली परेशानी से भी राहत मिलती है। पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल

रेलवे लाभार्थियों को बेहतर एवं सुलभ चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों के बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षित यात्रा,सुनिश्चित करने के लिए पेयजल गुणवत्ता निगरानी सुदृढ़

पश्चिम रेलवे द्वारा सितंबर और अक्टूबर 2026 के दौरान यात्री कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आरामदायक रेल यात्रा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, रेलवे स्टेशनों और रेलवे कॉलोनियों में व्यापक पेयजल गुणवत्ता निगरानी की और अधिक सुदृढ़ किया गया। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सुरक्षित पेयजल यात्री सुविधाओं का एक अनिवार्य घटक है। बच्चे, वरिष्ठ नागरिक और दैनिक यात्रियों सहित हजारों रेल उपयोगकर्ता अपनी यात्रा के दौरान स्टेशनों पर उपलब्ध पेयजल सुविधाओं पर निर्भर रहते हैं। स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना केवल स्वच्छता का उपाय नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य जिम्मेदारी भी है, जो यात्रियों को जलजनित बीमारियों से सुरक्षित रखती है और एक सुदृढ़ यात्रा अनुभव प्रदान करने में सहायक बनती है। श्री विनीत अभिषेक ने बताया कि 1



सितंबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 तक की पेयजल गुणवत्ता निगरानी रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम रेलवे के चिकित्सा विभाग द्वारा पूरे नेटवर्क में सघन परीक्षण अभियान चलाया गया। पानी के डिसइंफेक्शन की प्रभावशीलता का

मूल्यांकन करने के लिए किए गए कुल 15,936 रैसिड्यूअल क्लोरीन परीक्षणों में सभी 15,936 नमूने सफल पाए गए। इसी प्रकार, माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा के परीक्षण हेतु किए गए सभी 2,674 बैक्टीरियोलॉजिकल नमूनों की जांच भी

सफल रही। इस तरह दोनों ही श्रेणियों में 100% सफलता दर दर्ज की गई। रैसिड्यूअल क्लोरीन और बैक्टीरियोलॉजिकल विश्लेषण मिलकर संभावित संदूषण जोखिमों की पहचान करने और हर समय प्रभावी जल शोधन सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह उत्कृष्ट उपलब्धि नियमित सैपलिंग, समयबद्ध प्रयोगशाला जांच, सूक्ष्म निगरानी और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय के निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है। पश्चिम रेलवे का दायित्व केवल ट्रेनों के परिचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक यात्री के साथ-साथ रेलवे कॉलोनियों में रहने वाले रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य एवं कल्याण की रक्षा करना भी है। चिकित्सा विभाग पेयजल गुणवत्ता की निरंतर निगरानी बनाए रखेगा, स्वच्छता व शुद्धता के उच्च मानकों का पालन करेगा और सभी को एक सुरक्षित व स्वस्थ यात्रा प्रदान करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करेगा।



करने का प्रोत्साहनात्मक निर्णय लिया गया है। मंत्री ने आगे कहा कि ग्रामीण स्तर

पर ग्राम सेवक राज्य सरकार और किसानों के बीच एक कड़ी के रूप में बुनियादी कर्मचारी हैं। राज्य में

खातेदार किसानों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं और सहायता का

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से गुजरात दीपोत्सवी अंक विक्रम संवत-2082' का विमोचन किया गया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को गुजरात की साहित्य, कला एवं संस्कारों की विरासत को उजागर करने वाले गुजरात दीपोत्सवी अंक विक्रम संवत 2082 का विमोचन किया। राज्य के सूचना विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अपनी विशिष्ट परंपरा के अनुसार 'गुजरात दीपोत्सवी अंक' प्रकाशित किया जाता है। इस वर्ष गुजरात दीपोत्सवी-2082 में गुजरात के मूर्धन्य साहित्यकारों की सुजनशील लेखनी से प्रस्तुत साहित्य की सुगंध से पाठक मित्रों का मन प्रफुल्लित हो, ऐसे चिंतनपरक लेख, कविताएँ, लघुकथाएँ, हास्य-व्यंग्य रचनाएँ और लघु नाटकों से युक्त साहित्य का रसपूर्ण संग्रह प्रस्तुत किया गया है। सर्वश्री गुणवंतभाई शाह, विष्णुभाई पंड्या, डॉ. कुमारपाल देसाई, रघुवीरभाई चौधरी, शाहबुदीन राठौड़, रतिलाल बेरीसागर, माधव रामानुज और राजेंद्र शुक्ल जैसे प्रतिष्ठित साहित्यकारों की सुजनशील लेखनी से लिखी गई साहित्यिक कृतियाँ, दीपोत्सवी अंक में प्रकाशित की गई हैं। इस विशाल अंक में 28 अध्ययनपरक



लेख, 28 लघुकथाएँ, 16 हास्य-व्यंग्य रचनाएँ, 9 लघु नाटक और लगभग 89 काव्य रचनाएँ शामिल हैं। साथ ही, प्रकृति, लोकजीवन और मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाली लगभग 52 रंगीन

तस्वीरें और मनमोहक चित्र इस अंक को और अधिक नयनाभिराम बनाते हैं। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, सूचना एवं प्रसारण विभाग के

सचिव श्री विक्रान्त पांडे, अपर सूचना निदेशक डॉ. संजय कचोट, संयुक्त सूचना निदेशक श्री जयेश दवे सहित सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्थान में कांग्रेस की बैठक से पहले मौत का करंट, टेंट के पाइप में बिजली दौड़ने से दो की जान गई, 13 घायल

प्रतापगढ़। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में पंचायती राज चुनाव को लेकर आयोजित होने वाली कांग्रेस की बैठक से पहले बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। रेण्दा गांव में बैठक स्थल पर तेज हवा के कारण टेंट उड़ने लगा। टेंट को गिरने से बचाने और उसे संभालने के लिए वहां मौजूद लोगों ने उसके पाइप पकड़ लिए, लेकिन इसी दौरान टेंट का पाइप ऊपर से गुजर रही हाईटेशन बिजली की लाइन के संपर्क में आ गया। पाइप में करंट फैलते ही वहां मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। अचानक हुए इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य घायल हो गए। कुछ ही पलों में बैठक स्थल पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोग घायलों की मदद के लिए दौड़े और तत्काल एंबुलेंस बुलाकर उन्हें प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली।

जानकारी के अनुसार, रेण्दा गांव में पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक आयोजित की जानी थी। बैठक में स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की तैयारी थी। बताया गया कि आयोजन में करीब 150 से 200 लोगों के जुटने की संभावना थी। कार्यक्रम के लिए बैठक स्थल पर टेंट लगाया गया था, ताकि वहां आने वाले लोग बैठ सकें और चुनाव संबंधी

चोरवाड रोड स्टेशन पर सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस के प्रायोगिक ठहराव का शुभारंभ, जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

भावनगर मंडल के अंतर्गत चोरवाड रोड रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा एवं क्षेत्रीय रेल संपर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए ट्रेन संख्या 19218/19217 वेरावल-बान्द्रा सौराष्ट्र जनता दैनिक एक्सप्रेस के प्रायोगिक ठहराव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर माननीय सांसद, जूनागढ़ (लोकसभा) श्री राजेश चुडासमा, माननीय विधायक, मांगरोल श्री भगवानजीभाई लाखाभाई करगठिया तथा माननीय सरपंच गड्डु भी बावुभाई मोकरिया ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन संख्या 19218 वेरावल-बान्द्रा सौराष्ट्र जनता दैनिक एक्सप्रेस को रवाना किया। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चोरवाड रोड स्टेशन पर सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस के दोनों दिशाओं में प्रायोगिक ठहराव की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत ट्रेन संख्या 19218 वेरावल-बान्द्रा सौराष्ट्र जनता दैनिक एक्सप्रेस 21 अक्टूबर 2026 से चोरवाड रोड स्टेशन पर ठहर रही है। इस स्टेशन पर ट्रेन का आगमन समय 12:15 बजे तथा प्रस्थान समय 12:16 बजे निर्धारित है।

टोक्यो में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी का जापानी उद्योगों से गुजरात में निवेश के लिए आह्वान; प्रतिनिधिमंडल द्वारा 20 बैठकें और 2 राउंडटेबल संवाद

गांधीनगर, 21 अक्टूबर : आगामी वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के संदर्भ में जापान की यात्रा पर गए उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में गुजरात प्रतिनिधिमंडल ने आज टोक्यो में जापान के सरकारी अग्रणियों और प्रमुख उद्योग समूहों के साथ श्रृंखलाबद्ध बैठके आयोजित कीं।

एक ही दिन में गुजरात प्रतिनिधिमंडल ने :

» 20 महत्वपूर्ण बैठकें और 2 राउंडटेबल संवाद आयोजित किए।

» जापान के विदेश राज्य मंत्री, इवाते प्रीफेक्चर के गवर्नर और METI के डायरेक्टर जनरल के साथ चर्चा की।

» सुजुकी, JERA, टोक्यो इलेक्ट्रॉन, सुमिताोमो केमिकल, फुरुकावा इलेक्ट्रिक, मारुबेनी और लाइव नेशन सहित कंपनियों के साथ बैठके आयोजित कीं।

» सुजुकी के वेंडरों के साथ विशेष राउंडटेबल बैठक आयोजित की।

उप मुख्यमंत्री ने बैठकों में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहकर नेतृत्व प्रदान किया। इन संवादों का उद्देश्य गुजरात में नए निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग और औद्योगिक विस्तार के अवसरों को प्रोत्साहन देना था।

दिन की प्रमुख चर्चाएँ

» सरकारी नेतृत्व के साथ संवाद : गुजरात-जापान संबंध, व्यापार, निवेश और क्षमता निर्माण।

» सुजुकी : ऑटोमोबाइल क्षेत्र का विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहन और वेंडर पारस।

» JERA : स्वच्छ ऊर्जा, बिजली उत्पादन और ग्रीन ट्रांजिशन।

चर्चा की जा सके। बैठक शुरू होने से पहले आयोजन स्थल पर तैयारियां चल रही थीं और लोग धीरे-धीरे वहां पहुंच रहे थे। इसी बीच मौसम अचानक बदल गया और तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि टेंट हिलने लगा और उसके उड़ने का खतरा पैदा हो गया। टेंट को गिरने से बचाने के लिए वहां मौजूद लोग उसे संभालने में जुट गए। इसी कोशिश के दौरान एक ऐसी घटना हुई, जिसने पूरे आयोजन को शोक में बदल दिया।

टेंट को संभालने के लिए कुछ लोगों ने उसके पाइप पकड़ लिए। इसी दौरान पाइप ऊपर से गुजर रही हाईटेशन बिजली की लाइन के संपर्क में आ गया। बिजली की लाइन से संपर्क होते ही पाइप में करंट फैल गया और उसे पकड़े हुए लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसा अचानक हुआ, इसलिए वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही क्षणों में बैठक स्थल पर चीख-पुकार मच गई। लोग घायलों को बचाने और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए दौड़ पड़े। अचानक हुए इस घटनाक्रम से वहां मौजूद लोगों में भय और अफरा-तफरी फैल गई। चुनावी बैठक के लिए तैयार किया गया स्थल कुछ ही देर में राहत और बचाव के प्रयासों का केंद्र बन गया।

इस हादसे में मोहन मीणा और अर्जुन मीणा की मौत हो गई। दो लोगों की जान जाने की खबर से गांव में शोक टेंट लगाया गया था, ताकि वहां आने वाले लोग बैठ सकें और चुनाव संबंधी



सबसे पहली प्राथमिकता घायलों को अस्पताल पहुंचाने की रही। मौके पर मौजूद लोगों ने सहायता के लिए एंबुलेंस बुलवाई। इसके बाद 108 एंबुलेंस की मदद से घायलों को प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया। घायलों के परिजन भी घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल पहुंचे और अपने परिवार के सदस्यों की स्थिति के बारे में जानकारी लेने लगे। अचानक हुई इस दुर्घटना ने कई परिवारों को चिंता में डाल दिया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए

प्रशासनिक अधिकारियों ने भी तत्काल स्थिति का जायजा लिया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विजेश पंड्या और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयदेव सिंहाग जिला चिकित्सालय पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने घायलों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और उपचार की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। प्रशासन की ओर से घायलों के उपचार पर नजर रखी जा रही है। घटना के बाद हादसे की परिस्थितियों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, दुर्घटना से संबंधित

सभी पहलुओं और जिम्मेदारी को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक नानालाल निनामा भी इस बैठक में शामिल होने वाले थे। उनके पहुंचने से ठीक पहले हादसा हो गया। बैठक में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की तैयारी थी और पंचायती राज चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी थी। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में अचानक हुए हादसे ने पूरी योजना को प्रभावित कर दिया। बैठक शुरू होने से पहले ही दो

लोगों की मौत और 13 लोगों के घायल होने की खबर फैल गई। इसके बाद आयोजन स्थल पर शोक और चिंता का माहौल बन गया। लोगों का ध्यान चुनावी चर्चा से हटकर घायलों की मदद और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताने पर केंद्रित हो गया। इस घटना ने खुले स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में सुरक्ष व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विशेष रूप से उन स्थानों पर, जहां ऊपर से हाईटेशन बिजली की लाइनें गुजरती हैं, अस्थायी टेंट लगाने से पहले सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। टेंट के पाइपों और बिजली की लाइनों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करना और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखना ऐसे आयोजनों की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। तेज हवा में टेंट उड़ने या उसके ढांचे के अस्थिर होने की स्थिति में लोगों की ओर से उसे हाथों से संभालने का प्रयास भी जोखिम पैदा कर सकता है। बिजली की हाईटेशन लाइन के संपर्क में आने पर करंट तेजी से फैल सकता है और लोगों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। विशेषज्ञों की सामान्य सुरक्षा सलाह के अनुसार, बिजली की लाइन के संपर्क में आए किसी धातु के ढांचे को सीधे छूने से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में बिजली आपूर्ति बंद कराने के लिए संबंधित बिजली विभाग और आपातकालीन सेवाओं को तुरंत सूचना देना जरूरी होता है। बचाव के प्रयासों के दौरान भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि करंट की चपेट में आए व्यक्ति या बिजली से जुड़े ढांचे को सीधे छूने पर दूसरे व्यक्ति की जान भी खतरे में पड़ सकती है। रेण्दा गांव की घटना ने इस तरह के जोखिमों के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को फिर रेखांकित किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक बैठकों, सामाजिक समारोहों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के दौरान अस्थायी टेंट लगाए जाते हैं। ऐसे आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, लेकिन कई बार स्थान का चयन करते समय बिजली की लाइनों, मौसम और आपातकालीन निकासी जैसी व्यवस्थाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इस हादसे के बाद यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि बैठक स्थल पर टेंट लगाने से पहले बिजली की लाइन से सुरक्षित दूरी सुनिश्चित की गई थी या नहीं और तेज हवा की स्थिति में लोगों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम थे। इन सवालों के जवाब संबंधित जांच और प्रशासनिक पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे। रेण्दा गांव में हादसे के बाद मृतकों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिन लोगों के साथ बैठक में शामिल होने और चुनावी चर्चा करने की उम्मीद थी, उनके बीच अचानक मातम छा गया। घायलों के परिवार अस्पताल में उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। प्रशासन की निगरानी में घायलों का उपचार जारी है और घटना से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट करना आगे की कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण होगा।

पंचायती राज चुनाव को लेकर आयोजित होने वाली कांग्रेस की बैठक अब इस दर्दनाक दुर्घटना के कारण चर्चा में है। तेज हवा से टेंट उड़ने की आशंका को देखते हुए उसे संभालने की कोशिश में बिजली की हाईटेशन लाइन से संपर्क होना दो लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ, जबकि 13 अन्य घायल हो गए। यह हादसा याद दिलाता है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में छोटी दिखाई देने वाली सुरक्षा चूक भी गंभीर परिणाम ला सकती है। फिलहाल पूरे क्षेत्र की निगाह घायलों के स्वास्थ्य और घटना की परिस्थितियों की जांच पर टिकी है।

जीएसटी दरों में कमी के बावजूद गुजरात के राजस्व में अमृतपूर्व वृद्धि : पिछले वर्ष की तुलना में सितंबर-2026 में जीएसटी राजस्व में 35 प्रतिशत का भारी उछाल

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में जीएसटी दरों में की गई कमी के बावजूद गुजरात राज्य के जीएसटी राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में व्यापार-उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण और करदाताओं में स्वैच्छिक कर अनुपालन का दायरा बढ़ने के कारण गुजरात ने यह उपलब्धि हासिल की है।

कैबिनेट बैठक के बाद प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि पिछले महीने सितंबर-2026 में गुजरात को जीएसटी के तहत 8,167 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि अर्थात सितंबर-2025 में 6,050 करोड़ रुपए था। इस प्रकार; पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जीएसटी राजस्व में सीधे 35 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी राजस्व की वृद्धि दर 14.7 प्रतिशत रही है, जबकि इसकी तुलना में गुजरात की वृद्धि दर दोगुने से भी अधिक अर्थात 35 प्रतिशत रही है।



अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष 2026- 27 के प्रथम 6 महीनों अर्थात

पुलिस शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वीर शहीद पुलिसकर्मियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की अहमदाबाद में आयोजित हुआ पुलिस शहीद स्मृति दिवस

गांधीनगर : ख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जनता की सुरक्षा, संरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए द्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीद पुलिसकर्मियों को पुलिस शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पुलिस जवानों की निरंतर कर्तव्यनिष्ठा तथा उत्तम कानून-व्यवस्था के कारण गुजरात देश के ग्रीथ इंजन के रूप में स्थापित हुआ है। देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों के शौर्य, समर्पण और बलिदान को याद करने के लिए हर वर्ष 21 अक्टूबर को पूरे देश में पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। अहमदाबाद में आयोजित इस पुलिस शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर राज्य के शहीद पुलिसकर्मियों की नामावली का पठन किया गया। पुलिस बल द्वारा उन्हें अनुशासित ढंग से सम्मानपूर्वक सलामी दी गई, जबकि पुलिस बैंड द्वारा शोक धुन प्रस्तुत की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार के प्रमुख के रूप में अपने सेवाकाल के दौरान पुलिस बल के योगदान को सम्मानित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का निर्माण और पुलिस संग्रहालय की शुरुआत पूरे दिन के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात के विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर, उद्योगों के अनुकूल नीतियों, सरकारी सहायता और कारोबार करने में सुगमता के लिए उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। जापानी कंपनियों, निवेशकों और उद्योग जगत के अग्रणी प्रतिनिधियों को गुजरात में निवेश, विस्तार और दीर्घकालीन साझेदारी के अवसर तलाशने तथा आगामी वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट में भाग लेने के लिए हार्दिक आमंत्रण दिया गया।



पुलिसकर्मियों के बलिदान को सम्मान देने के साथ-साथ नई पीढ़ी को पुलिस बल की भूमिका तथा महत्त्व से परिचित कराने का एक प्रशंसनीय प्रयास है। गुजरात में हाल ही में नवरात्रि पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर मुख्यमंत्री ने पुलिस बल की कर्तव्यपरायणता को अभिनंदन देते हुए कहा कि राज्य के विकास एवं प्रगति के लिए सुरक्षित वातावरण अनिवार्य है। राज्य में शांति, सुरक्षा और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस बल की भूमिका अत्यंत

महत्त्वपूर्ण है। गुजरात के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की कर्तव्यपरायणता की सराहना करते हुए श्री पटेल ने वीर शहीद पुलिसकर्मियों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की। अहमदाबाद के शाहीबाग स्थित शहीद स्मारक में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद श्री दिनेशभाई मकवाणा, विधायक सर्वश्री डॉ. हसमुखभाई पटेल, कौशिकभाई जैन, अमूलभाई भट्ट, दिनेशसिंह कुशवाहा, केचनवेन

रादड़िया सहित सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर राज्य पुलिस महानिदेशक श्री जी. एस. मलिक, पुलिस महानिदेशक (जेनर) डॉ. के. एल. एन. राव, पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) नीराजा गोटर्ला, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गेहलोत, अपर पुलिस महानिदेशक खुशींद अहमद सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।